भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोक सभा
आतारांकित प्रश्न संख्या 327
दिनांक 04.02.2025 को उत्तरार्थ

असम में स्वामित्व

†327. **श्री प्रद्युत बोरदोलोई:**

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपया करेंगे कि:

(क) असम में "गावों का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण" (स्वामित्व) योजना के अंतर्गत शामिल किए जाने के लिए असम के लक्षित गावों की संख्या का ब्यौरा क्या है और राज्य सरकार को सौंपे गए मानचित्रों सहित कितने गावों की मैपिंग पूरी कर ली गई है;

(ख) योजना के आरंभ से असम में 'स्वामित्व' के अंतर्गत जारी की गई निधि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि असम में 'स्वामित्व' योजना के अंतर्गत 'जीरो प्रॉपर्टी कार्ड' तैयार किए गए हैं और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार ने असम में नदी के अत्यधिक कटाव के समाधान हेतु कोई तंत्र विकसित किया है और यह किस प्रकार भू-जोतों के आकार और संगठन को प्रभावित कर सकता है?

उत्तर

पंचायती राज राज्य मंत्री

(प्रोफ. एस. पी. सिंह बघेल)

(क) असम में सर्वेक्षण ऑफ विलेज आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन रूरल एरियाज (स्वामित्व) योजना के तहत कवरेज के लिए लक्षित 1,095 गांवों में से, 861 गांवों में मैपिंग का काम पूरा हो चुका है और 765 गांवों के नक्शे राज्य सरकार को सौंप दिए गए हैं।

(ख) स्वामित्व योजना के तहत असम सहित उन 31 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों, जिन्होंने योजना के कार्यान्वयन के लिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, में ड्रोन का उपयोग करके बड़े पैमाने पर मैपिंग (एलएसएम) और सतत संचालन संदर्भ स्टेशन (सीओआरएस) स्थापित करने के लिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग को भी धन जारी किया गया है जिसका विवरण निम्नलिखित है:

सी.ओ.आर.एस.*	₹ 1,16,54,14,455
एल.एस.एम.*	₹ 2,49,53,16,599

राष्ट्रीय परियोजना निगरानी इकाई (एन.पी.एम.यू.), स्थानिक नियोजन एप्लिकेशन 'ग्राम मानचित्रण' में वृद्धि, केंद्रीय बुनियादी ढांचे और अन्य तकनीकी और सॉफ्टवेयर आवश्यकताओं का समर्थन करने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एन.आई.सी.-सर्विसेज इनकॉर्पोरेशन के माध्यम से) को अब तक ₹35,00,40,987 भी जारी किए गए हैं।

इसके अलावा, सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) गतिविधियों और राज्य परियोजना निगरानी इकाइयों (एसपीएमयू) की स्थापना के लिए राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को धन भी प्रदान किया जाता है। SVAMITVA योजना की शुरुआत के बाद से, IEC और SPMU घटकों के तहत असम को जारी किए गए ₹ 1.09 करोड़ में से ₹ 61.64 लाख का उपयोग किया गया है।

(ग) हां, महोदय। स्वामित्व योजना के तहत असम में अभी तक कोई संपत्ति कार्ड तैयार नहीं किया गया है। राज्य वर्तमान में विस्तृत क्षेत्र सर्वेक्षण पूरा कर रहा है, सर्वेक्षण किए गए गैर-भूकर गांवों में नागरिकों से भूमि निपटान आवेदन प्राप्त कर रहा है, और जिला प्राधिकरण के माध्यम से इन आवेदनों पर कार्रवाई कर रहा है।

(घ) नहीं, महोदय। असम सरकार ने भूमि के आकार और संरचना पर नदी के कटाव की उच्च दरों को ध्यान में रखते हुए स्वामित्व योजना के भीतर अभी तक विशिष्ट तंत्र विकसित नहीं किया है। हालाँकि, असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का आपदा रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली (DRIMS) पोर्टल जिलों को कटाव की घटनाओं की रिपोर्ट करने की अनुमति देता है, जिससे प्रभावित कुल भूमि क्षेत्र का वार्षिक मूल्यांकन होता है।

***